

मुकदमों का विवरण

शशीकांत शर्मा और ओआरएस. वी.

उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर। (2023 की आपराधिक अपील संख्या 3663) 1 दिसंबर, 2023

[पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा और संदीप मेहता, जे. जे.]

हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:क्या प्रथम दृष्टया सामग्री

दंडनीय यू/एस।3(2)(v) अपीलार्थियों के खिलाफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम बनाया गया था।

दंड संहिता, **1860-एस. एस.147, 148, 149, 307, 323, 504** - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, **1989 -धारा 3 (2) (v)**-अपीलकर्ताओं ने शुरुआत में स्वीकार किया कि जहां तक भारतीय दंड संहिता सी. के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का संबंध है, निर्वहन के लिए प्रार्थना के लिए साक्ष्य के व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होगी और इसलिए, आदेश तैयार करने के आरोप को चुनौती देना छोड़ दिया गया था-हालांकि, धाराओं के तत्व।**3(2) (v)** एस. सी./एस. टी. अधिनियम की धारा प्रथम दृष्टया अभियुक्त अपीलार्थियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा स्वीकार किए गए आरोपों से नहीं बनती है।

आयोजित किया गया:अभियोजन पक्ष के उच्चतम मामले के अनुसार, आरोपी 'वी. यू.' ने 'आर' पर बंदूक से गोली चलाई, जिसने उसे बाईं जांघ में मारा-एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत अपराध के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले में किया गया एकमात्र प्रक्षेपण यह था कि गवाह 'वी. के.' अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य होने के नाते आरोपी अपीलार्थियों द्वारा 'आर' पर गोली के लाल होने के बाद जातिवादी दुर्व्यवहार का शिकार हुआ था-हालांकि, मेडिकोलेगल रिपोर्ट में कहा गया था कि आर की जांघ पर एक फोड़ा/फोड़ा देखा गया था और बंदूक की गोली का कोई सबूत नहीं मिला था-एस के नंगे अवलोकन से।3(2)(v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत, यह स्पष्ट है कि अपराध का गठन करने के लिए, यह आरोप होना चाहिए कि आरोपी ने अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं होने के कारण भारतीय दंड संहिता सी. के अंतर्गत अपराध किया है जो 1068 के खिलाफ 10 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए दंडनीय है।

[2023] 15 एस सी आर।

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति ऐसे 'समुदाय' से संबंधित है-जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि घटना में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के निहितार्थ थे-चाहे वह अभियोजन के उच्चतम मामले के अनुसार हो, भारतीय दंड संहिता सी. के अंतर्गत 10 साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय एकमात्र अपराध है। 307 भारतीय दंड संहिता सी. अभियुक्त 'वी. यू.' द्वारा 'आर.' पर कथित रूप से की गई बंदूक की गोली के आधार पर लागू की गई है, जिसके परिणामस्वरूप कोई संबंधित चोट नहीं आई है-रिकॉर्ड पर पूरी सामग्री को देखने के बाद, यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किए गए स्वीकार किए गए मामले से, ऐसा कोई आरोप नहीं है कि भारतीय दंड संहिता सी. के अंतर्गत 10 साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित व्यक्ति पर उच्च जाति के आरोपी द्वारा इस जानकारी के साथ किया गया था कि ऐसा व्यक्ति उक्त समुदाय का था। [पैरा 14,15,16,17]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

सुरेश @पप्पु भूधरमल कलानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, आकाशवाणी

(2001) एस. सी. 1375-निर्दिष्ट।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील संख्या 3663।

2023 के सी. आर. एल. ए. No.3107 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के दिनांकित 06.04.2023 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

आर. बसंत, वरिष्ठ अधिवक्ता, नीरज के. शर्मा, प्रियंका शर्मा, हरेंद्र सिंह, पवन कुमार शर्मा, अमित श्रीवास्तव, पी. शर्मा, शरत, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

शरण देव सिंह ठाकुर, ए. ए. जी., संजय हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री श्वेताश्व अग्रवाल, संचित गार्गा, सुश्री मिथु जैन, कुणाल राणा, सुश्री स्नेहा गोस्वामी, सुश्री रुचिरा गोयल, अविरल सक्सेना, शरण्या सिन्हा, हर्ष प्रताप शाही, मुस्तफा सज्जाद, अदित जायेशभाई शाह, सुश्री कीर्ति जया, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

1069

शशीकांत शर्मा और ओआरएस. वी. उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर।

मेहता, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (इसके बाद 'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 14 ए (1) के अंतर्गत अभियुक्त अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आपराधिक अपील संख्या 3107/2023 को खारिज करते हुए 6 अप्रैल, 2023 के आदेश की वैधता और वैधता पर सवाल उठाते हुए अभियुक्त अपीलकर्ताओं द्वारा तत्काल अपील की गई है। विद्वत अपीलीय न्यायालय ने सत्र मामला संख्या 228/2021 में विद्वत विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, हाथरस द्वारा 14 मार्च, 2023 को पारित आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 227 (इसके बाद 'सीआरपीसी' के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) के अंतर्गत अभियुक्त अपीलार्थियों के नेतृत्व में आरोपमुक्त करने के आवेदन को खारिज कर दिया गया और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 147, 148, 149, 307, 323, 504 (इसके बाद 'आईपीसी' के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए उनके खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया गया। उक्त आदेश द्वारा, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने यह भी निर्देश दिया कि अभियुक्त अपीलार्थी नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

3. यह उल्लेख किया जा सकता है कि 19 मई 2023 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने निर्देश दिया था कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित 2 सितंबर, 2022 के आदेश के अनुसरण में अभियुक्त अपीलार्थियों द्वारा निष्पादित बांड लागू रहेंगे और गैर-जमानती वारंट जो उस स्तर पर जारी किए गए थे, उन्हें आगे के विचार तक निष्पादित नहीं किया जाएगा।

4. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने शुरुआत में स्वीकार किया कि जहां तक भारतीय दंड संहिता सी. के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का संबंध है, आरोपमुक्त करने की प्रार्थना के लिए साक्ष्य के व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होगी और इसलिए, उन्होंने आरोपी अपीलार्थियों की ओर से आदेश तैयार करने के लिए दी गई चुनौती को छोड़ दिया। हालांकि, विद्वान वरिष्ठ वकील का प्रबल तर्क था कि एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के तत्व अभियोजन पक्ष के स्वीकृत आरोपों से आरोपी अपीलार्थियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया नहीं बनाए गए हैं और इसलिए, आरोपी अपीलार्थी इस न्यायालय के हस्तक्षेप के हकदार हैं और आक्षेपित आदेश इस हद तक हस्तक्षेप करने के लिए उत्तरदायी हैं।

[2023] 15 एस सी आर।

5. विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के अंतर्गत अपराध साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष का एक विशिष्ट आरोप होना चाहिए कि आरोपी ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है, यह जानते हुए कि पीड़ित ऐसे समुदाय से है। आक्षेपित आदेशों, एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोपों और सी. आर. पी. सी. की धारा 161 के अंतर्गत जांच के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयानों का उल्लेख करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया कि अभियोजन पक्ष के सर्वोच्च मामले के अनुसार, आरोपी विनोद उपाध्याय ने रिकू ठाकुर पर बंदूक से गोली चलाई जो उसकी बाईं जांघ में लगी। एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत अपराध के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले में केवल यह अनुमान लगाया गया था कि गवाह विरेंद्र कुमार को एससी समुदाय का सदस्य होने के नाते रिकू ठाकुर पर गोली चलाने के बाद आरोपी अपीलकर्ताओं द्वारा जातिवादी दुर्व्यवहार का शिकार बनाया गया था। उन्होंने आग्रह किया कि भारतीय दंड संहिता सी. के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए अपराधों के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा जोर रिकू ठाकुर पर केंद्रित है और इस प्रकार, एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी अपीलार्थियों के खिलाफ विरचित गए आरोप का कोई तथ्यात्मक या कानूनी आधार नहीं है।

6. उपरोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, विद्वान वरिष्ठ वकील ने आग्रह किया कि पूरा अभियोजन मामला झूठा और मनगढ़ंत है और राजनीतिक प्रतिशोध के कारण जवाबी हमले के रूप में दर्ज किया गया है। उन्होंने आग्रह किया कि प्राथमिकी और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित सिद्धांत कि रिकू ठाकुर को बांह में चोट लगी थी, मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा तैयार की गई मेडिकोलेगल रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से गलत है, जिन्होंने रिकू ठाकुर की जांच की थी और कहा था कि उनकी जांघ पर फोड़ा/फोड़ा देखा गया था और बंदूक की गोली का कोई सबूत नहीं मिला था।

7. उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह शिकायतकर्ता पक्ष के सदस्य हैं जिन्होंने आरोपी अपीलार्थियों की ओर से पुष्पेंद्र की हत्या की और उसके बाद, बचाव करने के लिए, मनगढ़ंत आरोपों पर आरोपी अपीलार्थियों के खिलाफ स्पष्ट रूप से झूठा आपराधिक मामला दर्ज किया गया। इन आधारों पर, विद्वान वरिष्ठ वकील ने न्यायालय से अपील को स्वीकार करने और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी अपीलार्थियों के खिलाफ विरचित गए आरोप की सीमा तक आक्षेपित आदेशों को उलटने का आग्रह किया।

8. इसके विपरीत, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान ए. ए. जी. और शिकायतकर्ता प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील नं. 2 ने 1071 के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों का जोरदार और उत्साहपूर्वक विरोध किया।

शशीकांत शर्मा और ओआरएस. वी. उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर। [संदीप मेहता, जे।] याचिकाकर्ता। यह प्रस्तुत किया गया था कि अभियुक्त अपीलकर्ताओं ने शिकायतकर्ता पक्ष के सदस्यों पर केवल इसलिए हमला किया क्योंकि वे दूसरे राजनीतिक दल के लिए प्रचार कर रहे थे।

9. न्यायालय को विशेष न्यायाधीश द्वारा इस आरोप के विशेष संदर्भ में पारित आदेश के माध्यम से लिया गया था कि जांच अधिकारियों पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत नकारात्मक रिपोर्ट देने के लिए दबाव डाला गया था। अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करते हुए, आरोपी व्यक्ति प्राथमिकी दर्ज करने में बाधा डालने में भी कामयाब रहे और न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद, प्राथमिकी दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश सरकार में एक पूर्व कैबिनेट मंत्री के कहने पर जांच में हेरफेर किया गया था। उन्होंने आग्रह किया कि सीआरपीसी की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए विरेन्द्र कुमार के बयान से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा रिकू ठाकुर पर गोली चलाने के बाद, उन्होंने गवाह की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और उसकी ओर जाति आधारित गालियां दीं और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

10. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए. ए. जी. और शिकायतकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार, एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोप और सी. आर. पी. सी. की धारा 161 के अंतर्गत जांच किए गए गवाहों के बयान स्पष्ट रूप से कथित अपराधों के आवश्यक तत्वों का खुलासा करते हैं और उनके अनुसार, आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने याचिका को खारिज करने की मांग की। इन मौखिक प्रस्तुतियों को आगे लिखित प्रस्तुतियों द्वारा पूरक किया गया है जो वस्तुतः न्यायालय के समक्ष जो तर्क दिया गया था उसकी पुनरावृत्ति है।

11. हमने बार में विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है। 12. शुरुआत में, इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि राज्य की ओर से लिखित प्रस्तुतियों में, अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाई गई प्रासंगिक याचिका कि एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आवश्यक तत्व अभियोजन पक्ष के स्वीकृत आरोपों से नहीं बनाए गए हैं, का स्पष्ट रूप से विरोध नहीं किया गया है। राज्य के वकील द्वारा लिखित प्रस्तुतियों में उद्धृत निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि आरोप तैयार करने के चरण में, न्यायालय को साक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है और यहां तक कि गंभीर संदेह भी आरोप तैयार करने के लिए पर्याप्त

है। फिर भी, उदाहरणों की एक लंबी कतार भी है कि अभियोजन पक्ष के स्वीकृत साक्ष्य से, जैसा कि दस्तावेजों में दर्शाया गया है, 1072 का नेतृत्व किया।

/

[2023] 15 एस सी आर।

जांच अधिकारी द्वारा धारा 173 सी. आर. पी. सी. के अंतर्गत रिपोर्ट में, यदि अपराध के लिए आवश्यक सामग्री नहीं बनाई जाती है, तो न्यायालय अभियुक्त के खिलाफ इस तरह के अपराध के लिए आरोप तय करने के लिए बाध्य नहीं है। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है -

सुरेश @पप्पु भूधरमल कलानी बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला

ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 1375 में रिपोर्ट किया गया। 13. अभियुक्त अपीलार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील ने एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के अंतर्गत बनाए गए आरोप की सीमा तक उनकी दलीलों को सीमित कर दिया था। अतः उक्त प्रावधान की भाषा पर विचार करने की आवश्यकता है और विरचित संदर्भ के लिए इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“3. अत्याचारों के लिए दंड।

(2) जो कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, -

... न्या।

(v) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अंतर्गत किसी व्यक्ति या संपत्ति के खिलाफ दस साल या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध करता है, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है, आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। ”

14. प्रावधान के एक नंगे अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रावधान का गठन करने के लिए, यह आरोप होना चाहिए कि आरोपी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं होने के कारण उसने अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 10 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए दंडनीय अपराध किया है, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति ऐसे 'समुदाय' से संबंधित है।

15. जाँच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि इस घटना में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के निहितार्थ थे। इस स्तर पर, हम ध्यान दे सकते हैं कि हालांकि अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी अपीलकर्ताओं के खिलाफ विरचित गए आरोप को चुनौती देना छोड़ दिया, लेकिन तथ्य यह है कि जब गवाह रिकू ठाकुर, जिसने आरोप लगाया था कि

आरोपी विनोद उपाध्याय ने उसे गोली मार दी थी, की चिकित्सकीय जांच की गई थी, तो उसके व्यक्ति पर कोई बंदूक की गोली की चोट नहीं देखी गई थी।

1073

शशीकांत शर्मा और ओआरएस. वी.उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर। [संदीप मेहता, जे।]

16. चाहे जो भी हो, अभियोजन पक्ष के उच्चतम मामले के अनुसार, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत 10 साल या उससे अधिक के कारावास के साथ दंडनीय भारतीय दंड संहिता सी. के अंतर्गत एकमात्र अपराध रिकू ठाकुर पर आरोपी विनोद उपाध्याय द्वारा कथित रूप से गोली चलाने के आधार पर लागू किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कोई संबंधित चोट नहीं आई है। अभिलेख पर संपूर्ण सामग्री के अवलोकन के बाद, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित स्वीकार किए गए मामले में, ऐसा कोई आरोप नहीं है कि भारतीय दंड संहिता सी. के अंतर्गत 10 साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध अनुसूचित जाति समुदाय के किसी व्यक्ति पर उच्च जाति के आरोपी द्वारा इस जानकारी के साथ किया गया था कि ऐसा व्यक्ति उक्त समुदाय का था।

17. इसलिए, अपीलार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील के इस तर्क में योग्यता है कि एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के प्रथम दृष्टया तत्व अभियोजन के स्वीकृत आरोपों से नहीं बने हैं और इस हद तक, आरोपी अपीलार्थियों के खिलाफ विरचित गया आरोप निराधार है।

18. नतीजतन, एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी अपीलार्थियों के खिलाफ विरचित गए आरोप की सीमा तक आक्षेपित आदेश और अपील को खारिज करने वाले आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। हालांकि, शेष अपराधों के लिए अभियुक्तों पर मुकदमा जारी रहेगा। अभियुक्त अपीलार्थी पहले से ही बांड पर रिहा हैं जैसा कि इस न्यायालय द्वारा 19 मई, 2023 को पारित आदेश में संकेत दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए बॉन्ड मुकदमे के समापन तक लागू रहेंगे। निचली न्यायालय द्वारा अभियुक्त के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को निरस्त कर दिया जाता है। एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए आरोप को रद्द करने के परिणामस्वरूप, और चूंकि शेष आरोप भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए हैं, इसलिए मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय से सत्र न्यायालय को स्थानांतरित कर दी जाएगी, जिसे मामले की सुनवाई करने की अधिकारिता है।

19. अपील की अनुज्ञात ऊपर दी गई है।

20. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील अनुज्ञात ।

अंकित ज्ञान